करना है । इसके अतिरिक्त, 32 माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय सहायता भी दी गई है जिससे कि उन्हें मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करने के योग्य बनाया जा सके ।

(ग) वर्ष 1986-89 के दौरान मध्य प्रदेश के लगभग 84,000 शिक्षकों को दस-दिवसीय अनुस्थापन शिविरों के जरिए शामिल किया गया है । राज्य के 30 जिलों के लिए जि0 शि0 प्र0 संस्थान संस्वीकृत किए गए जिनमें 20 प्रतिशत से अधिक की जनजातीय जनसंख्या वाले निम्नलिखित जिलों को शामिल किया गया है :—

झाबुआ, बेतुल, रतलाम, बस्तर, बिलासपुर, रायगढ़, मण्डला, शाहडोल, सरगुजा, पश्चिम-निमाड़ सिद्धी और सिग्रोनी ।

देश में इंजीनियरिंग कालेज

111. **श्री अजीत जोगी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्थित प्राइवेट और सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या और उनकी क्षमता के बारे में कोई आंकलन किया गया है, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि प्रति वर्ष इन कालेजों में प्रशिक्षित होने वाले इंजीनियरों की संख्या देश की आवश्यकता के अनुरूप है अथवा नहीं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में प्रशिक्षित इंजीनियरों की संख्या आवश्यकता से अधिक है और कुछ राज्यों में आवश्यकता से कम है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(ङ) क्या सरकार मध्य प्रदेश में कोई नया इंजीनियरी कालेज खोलने पर विचार कर रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री साथ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (प्रो० एम० जो० के० नैनन) : (क) से (घ) उत्तीर्ण इंजीनियरी स्नातकों के राज्यवार आंकड़े एकत्र किए जाते हैं तथा निजी तथा राजकीय इंजीनियरी कालेजों—दोनों के संबंध में नई दिल्ली स्थित अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान के तत्वाधान में राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति संसूचना प्रणाली के कार्यक्रम के अंतर्गत इन स्नातकों को खपाने के लिए अनुमान तैयार किए जाते हैं । इन आंकड़ों की तुलना से संबंधित आंकड़े रोजगार मार्किट में इनकी मांग को स्पष्ट करने तथा विषयक्षेत्रों में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े भी तैयार किए जाते हैं । अनुप्रयुक्त जनशक्ति संस्थान में ब्यौरेवार दस्तावेज प्रकाशित किए जाने हैं और उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा ।

इंजीनियरी स्नातकों के अधिक अथवा कमी से संबंधित अनुबंध सभी राज्यों में समान नहीं होते हैं । प्रत्येक राज्य में समान वर्ग के इंजीनियरों में कुछ बेरोजगारी विद्यमान होती है जबकि अन्य वर्गों के संबंध में ऐसा नहीं होता ।

अतः इस प्रकार एकत्रित आंकड़े राज्य आयोजन प्राधिकारियों को उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और आयोजना आयोग के विचारार्थ वे राज्य में तकनीकी शिक्षा के विकास की योजना तैयार कर सकें ।

(ङ) इस समय मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में नया इंजीनियरी कालेज को आरंभ करने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है ।

Manufacture of light combat aircraft

112. SHRI SURESH KALMADI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the latest position regarding manufacture of Light Combat Aircraft;